



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2014/चैत्र 27, 1936

No. 102]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2014/CHAITRA 27, 1936

### वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(महानिदेशालयपाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2014

### जांच की शुरुआत

(निर्णयिक समीक्षा)

**विषय :** चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और अमरीका से स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णयिक समीक्षा जांच की शुरुआत।

संख्या 15/04/2014-डीजीएडी.—यत टैरिफ अधिनियममें यथासंशोधित सीमा शुल्क 1995 वर्ष :, औं का अभिज्ञानपाटित वस्तु) टैरिफऔर यथासंशोधित सीमा शुल्क 1975, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारणनियमावली (, आगे जिन्हें) प्राधिकारीन में रखते हुए निर्दिष्टको द्या 1995 24 ने दिनांक (प्राधिकारी कहा गया है.11. की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना संख्या 2009 14/06/2008-डीजीएडी के तहत चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और अमरीकातक की .मी.मि 4 के मूल के या वहां से निर्यातित (द्व देश भी कहा गया है आगे सम्बजिन्हें) फ्लैट रोल्डल के कोल्डनलैस स्टीतक की चौड़ाई के स्टे .मी.मि 1250 से .मी.मि 600 मोटाई के सभी शृंखलाओं के लगाने की सिफारिश की। दों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कउत्पा (रिड्यूज्डकोल्ड) रोल्डत गढ़े गए कोल्डश्चातत्प 20 जांच परिणाम के आधार पर केंद्र सरकार ने दिनांकउत्पा.2.14 की अधिसूचना संख्या 2010/2010-सीमा शुल्क के तहत सम्बद्ध देशों से आयातित सम्बद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया। इससे पूर्व

प्राधिकारी ने मार्च 27,14 के अपने प्रारंभिक जांच परिणाम संख्या 2009/06/2008-डीजीएडी और अप्रैल 22, लगाने की के पाठित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्कद्व वस्तुद्व देशों से सम्बके शुद्धि पत्र के तहत सम्ब 2009 22 सिफारिश की और केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल, 38 अधिसूचना संख्याकी सीमा शुल्क 2009/2009-सीमा शुल्क, जिसे मई 30, 56 की अधिसूचना संख्या 2009/2009-सीमा शुल्क के तहत आगे संशोधित किया गया था, के तहत अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था। प्राधिकारी ने सम्बद्ध देशों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की एक मध्यावधि समीक्षा की और अंतिम जांच परिणाम दिनांक 8.6.15 की अधिसूचना संख्या 2001/16/2010-डीजीएडी के तहत जारी किए गए थे और उक्त जांच परिणाम के आधार पर केंद्र सरकार ने 6.9. की सीमा 2011 86 अधिसूचना संख्या शुल्क/द्व देशों से आयातितके तहत सम्ब 2011 सम्बद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क 2011<sup>वर्व</sup> में एक आदेश जारी किया जिसके तहत दिनांक 5.12. के दायरे से पके शुद्धि पत्र के तहत पाटनरोधी शुल्क 2011<sup>वर्व</sup> में अपवर्जित उत्पादों में कुछ संशोधन किए गए थे। केंद्र सरकार ने दिनांक 7.2. की शुद्धिपत्र अधिसूचना के 2012 तहत प्राधिकारी के संशोधित अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे।

### समीक्षा के लिए अनुरोध

2. यतअधिनियम (संशोधन) टैरिफसीमा शुल्क :,)क9 की धारा 19955 के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क (वर्ष की समाप्ति पर 5 न किया जाए तो वह इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख सेयदि उसे पूर्व में समाप्त उपाय की समाप्ति कीभावी हो जाएगा और प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से उक्तनिष्ठ तारीख से उचित समयावधि के भीतर किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर इस आशय की समीक्षा करनी अपेक्षित होती है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

3. और यत उपबंधों के अनुसार भारत मउपर्युक्त :०० सम्बद्ध वस्तु के एक प्रमुख विनिर्माता मैसर्स जिंदल स्टेनलैस लि20 ने दिनांक 0.2.14 मंत्रालय की अधिसूचना संख्याकी वित्त 2010/2010-सीमा शुल्क के आयातों पर पूर्व में लगद्व वस्तुद्व देशों के मूल की या वहां से निर्यातित सम्बके तहत सम्ब (यथासंशोधित)ाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णयिक समीक्षा का अनुरोध करते हुए एक विधिवत पुष्टिकृत आवेदन के साथ प्राधिकारी से संपर्क किया और सम्बद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की मांग की। इस अनुरोध के आधार ये हैं कि सम्बद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु का पाटन सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद जारी है और घरेलू उद्योग को सम्बद्ध देशों से हो रहे पाटन के कारण क्षति हो रही है। आवेदक ने आगे यह तर्क दिया है कि सम्बद्ध देशों के खिलाफ उक्त उपाय समाप्त किए जाने से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

4. और आवेदक द्वारा प्रदत्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी यह मानते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बारे में निर्णयिक समीक्षा कार्वाई की शुरुआत सम्बद्ध देशों से हुए पाटन की समाप्ति हेतु ऐसे शुल्क को जारी रखने की जरूरत की जांच करने और इस बात की जांच करने के लिए उचित होगी कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने या उसमें परिवर्तन किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

### घरेलू उद्योग और उसका आधार

5. यह आवेदन संबद्ध वस्तु के एक बड़े उत्पादक मैसर्स जिंदल स्टेनलैस लि 0(जिसे आगे घरेलू उद्योग या आवेदक कहा गया है) द्वारा दायर किय (ा गया है। सम्बद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाली तीन अन्य कंपनियां अर्थात मैसर्स बी आर जी, मैसर्स शाह एलौएज और मैसर्स सलेम स्टील प्लांट हैं। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है और वह वर्तमान निर्णयिक समीक्षा हेतु आवेदन दायर करने के आधार की अपेक्षा को भी पूरा करता है। आवेदक नियम 2(ख के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग भी है। (

## विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुएं

6. मूल जांचों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपनी अंतिम सिफारिशों में शुल्क के दायरे को केवल तक .मी.मि 1250 नुसार द को निम्ना चौड़ाई भी शामिल है। विचाराधीन उत्पाकी चौड़ाई पर ही सीमित रखा था जिसमें उक्त :परिभाषित किया गया था

"तक की चौड़ाई के .मी.मि 1250 से .मी.मि 600 तक की मोटाई के सभी शृंखलाओं के .मी.मि 4 फ रोल्डल के कोल्डनलैस स्टीस्टेलैट तत्पश्चात गढ़े गए कोल्ड रोल्ड द हैंउत्पा ( रिड्यूज्डकोल्ड) । सम्बद्ध वस्तु में उत्पाद के दायरे से निम्नलिखित अपवर्जन होंगे :

- i. मैसर्स थिसेनकृप स्टेनलैस इंटरनेशल, जर्मनी द्वारा आपूर्त ग्रेड ए आई एस आई हाई 420 )कार्बन0.28% -0 .40%420 ग्रेड (, ग्रेड बी ए 430, ग्रेड ए आई एस आई और ग्रेड ए आई एस 441 443 आई
- ii. ड्यूलेक्स स्टेनलैस स्टील ग्रेड 2205(एस 31803), 2304 (एस 32304), ई एन 1.4835, 1 .4547, 1.4539, 1 .4438, 1 .1 और 4318.1 और फेरिटिक ग्रेड ई एन 4833.1 और 4509. 4512
- iii. चीनी ताइपेर्ई की मैसर्स (ताइवान) यीह यूनाइटेड स्टील कार्पर्ड (यूस्को) .0 आरा उत्पादित एवं आपूर्त वस्तु के संबंध में भारतीय पेटेंट संख्या ल द जिसमें क्रोमियम निक्कके अंतर्गत आपूर्त उत्पा 223848 मैगनीजतथ 1 न निकल शामिल है और जो ग्रेड वाई यूल वाली न्यूनलैस स्टीनिटिक स्टेकापर आस्टे -0 वाई यू का घोतक है। 4"

7. बाद में घरेलू उद्योग ने मध्यावधि समीक्षा हेतु एक आवेदन दायर किया। आवेदन के आधार पर और विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 8.6.15 की अधिसूचना संख्या 2011/16/2009-डीजीएडी के तहत अपने अंतिम जांच परिणामों वधि समीक्ष्या) प्राकी सिफारिश की जिनके तहत विचाराधीन ( लिखित संशोधन किए गए थे। बाद में निम्नउत्पा

") :(क)+ (30 मिसे .मी.मि 1250 अथवा उससे अधिक परंतु .मी.मि 1000 की चौड़ाई की सह्य सीमा .मी. ल के मिल एज्डनलैस स्टी चौड़ाई के स्टेअनथिक के विनिर्दिष्ट, कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर लागू होगी।

) :(ख)+ (4 मिसे .मी.मि 1250 अथवा उससे अधिक परंतु .मी.मि 1000 की चौड़ाई की सह्य सीमा .मी. ल के ट्रिम एज्डनलैस स्टी चौड़ाई के स्टेअनथिक के विनिर्दिष्ट, कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर लागू होगी।"

8. इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार एक समीक्षा की जिसके परिणामस्वरूप 5.12. के दायरे से पूर्व में अपवर्जित के शुद्धि पत्र के तहत पाटनरोधी शुल्क 2011 न में रखते हुए इ को ध्यादों में कुछ संशोधन किए गए थे। उपर्युक्तउत्पास समीक्षा के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार परिभाषित है :

" हेतुमिल एज्ड) तक की मोटाई .मी.मि 4 + हेतु एज्डऔर ट्रिम्ड .मी.मि 30 +की चौड़ाई की .मी.मि 4 फ रोल्डतक की चौड़ाई के कोल्ड .मी.मि 1250 से .मी.मि 600 के सभी शृंखलाओं के (सह्यसीमालैट, पुनगढ़कर :दउत्पा ( रिड्यूज्डकोल्ड) रोल्डकोल्ड" जिनमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :

- i. .मी.मि 1250जमा सह्यसीमा छ वस्तुसे अधिक की चौड़ाई की सम्ब (

- ii. ग्रेड एआईएसआई हाईकार्बन 420,443 ,441 , ई एन 1.4835, 1 .4547, 1 .4539, 1 .4438, 1.4318, 1 .1 और ई एन 4833. 4509
- iii. चीनी ताइपेर्स दित एवं आपूर्त द्वारा उत्पा (यूस्को) .ल कार्पकी मैसर्स यीह यूनाइटेड स्टी (ताइवान) ल द जिसमें क्रोमियम निक्कके अंतर्गत आपूर्त उत्पा 223848 के संबंध में भारतीय पेटेंट संख्यावस्तु नलैस सनिटिक स्टेकापर आस्टे - मैगनीज्‌टील वाली न्यून निकल शामिल है और जो ग्रेड वाई यू 1 का द्वातक है। 4 तथा वाई यू

उक्त उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,7219 के शीर्ष 1975 .के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रयोग हवाइट 00 गुड्स, प्रोसेस उपकरण, डेयरी उपकरण, आटोमोटिव संघटक, रेल कार, मैट्रो कोच, वास्तुकला, भवन, रसोई उत्पाद एवं निर्माण आदि में किया जाता है।

9. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहेगा जैसा कि मध्यावधि समीक्षा के दौरान यथासंशोधित मूल अंतिम जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद और माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र है।

10. इसके अलावा आवेदक ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद और सम्बद्ध देशों से भारत में आयातित सम्बद्ध वस्तु पाटनरोधीन नियमों के अर्थ के भीतर समान वस्तुएं हैं; कि सम्बद्ध देशों से आयातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है; कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और सम्बद्ध देशों से आयातित सम्बद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी उत्पाद की अनिवार्य विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है; कि उपभोक्ता दोनों का अदलबदलकर उपयोग कर सकते हैं और वे कर रहे हैं और यह कि दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। जांच के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु सम्बद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु है।

### सम्बद्ध देश

11. वर्तमान आवेदन चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और अमरीका (द्व देश भी कहा गया है आगे सम्बजिन्हें) से विचाराधीन उत्पाद के आरोपित सतत पाटन के संबंध में दायर किया गया है।

### सामान्य मूल्य

12. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि भारतीय पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत चीन जन को गैर बाजार .गण. अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के कारण चीन जन का निर्धा मूल्यहेतु सामान्य .गण.रण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। यह दावा किया गया है कि किसी गैर 7 वाले देश के मामले मेवस्थाबाजार अर्थव्यं सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्रथम विकल्प के रूप में एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन करना अपेक्षित होता है। याचिकाकर्ता ने प्रस्ताव किया है कि दक्षिण कोरिया को उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में लिया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संयंत्रों की औसत क्षमता, लागत संरचना, उत्पादन प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी चीन में पाई गई इन चीजों से यथोचित और निष्पक्ष रूप से अत्यधिक मिलती जुलती हैं और यह भी सच है कि दक्षिण कोरिया स्थानीय उत्पादकों के भीतर तथा आयातित वस्तु के साथ पर्याप्त प्रतिस्पर्धा वाला एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। चीन जन400 तथा 300 का दावा समायोजनों के साथ मूल्यके लिए सामान्य .गण. शृंखलाओं के लिए एमईपीएस

स्टेनलैस स्टील रिव्यू में दक्षिण कोरिया (मासिक धातु बुलेटिन) के लिए उद्घृत कीमतों के आधार पर किया गया है। तथापि, जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ चीन जन का निर्धारण उपलब्ध मूल्य के सामान्यद्वारा वस्तुके लिए सम्ब. गण. के परिकलन मूल्य कराई गई सूचना के आधार पर सामान्यसूचना के आधार पर अर्थात् घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध द्वारा किया गया है।

13. ताइवान, कोरिया गणराज्य, अमरीका और ई यू में विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ताओं ने समायोजनों के साथ 400 तथा 300 शृंखलाओं के लिए एमर्झीपीएस स्टेनलैस स्टील रिव्यू में (मासिक धातु बुलेटिन) उद्घृत कीमतों का हवाला दिया है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि वे थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका हेतु प्रकाशित कीमतों को हासिल करने में समर्थ नहीं रहे हैं, इसलिए उन्होंने इन दोनों सम्बद्ध देशों में सामान्य मूल्य का दावा क्रमशताइवान एवं ई यू के लिए समायोजनों के साथ 400 तथा 300 शृंखलाओं के लिए एमर्झीपीएस स्टेनलैस स्टील रिव्यू को लेते हुए किया है। (मासिक धातु बुलेटिन)

14. यह नोट किया जाता है कि आवेदक किसी भरोसेमंद स्रोत से 200 शृंखला और डुप्लेक्स की कीमतें प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है। अत सूचना के आधार आवेदक ने उपलब्ध : पर सामान्य मूल्य का परिकलन कर सभी सम्बद्ध देशों के लिए 200 शृंखला और डुप्लेक्स का सामान्य मूल्य परिकलित किया है।

15. जांच करने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि सम्बद्ध देशों में सम्बद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है।

### निर्यात कीमत

16. भारत में आयातों की मात्रा और मूल्य का आकलन करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने साइबेक्स एकिजम से सूचना का प्रयोग करते हुए निर्यात कीमत निर्धारित की है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन और बिक्री कमीशन के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं। जांच करने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि सम्बद्ध देशों में सम्बद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है।

### पाठनमार्जिन

17. समीक्षा जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए याचिकाकर्ता ने इस आशय का पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किया है कि सम्बद्ध देशों में सम्बद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि सम्बद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु का पाठन जारी है।

### पाठन एवं क्षति जारी रहना या उसकी पुनरावृत्ति होना

18. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को प्रतिकूल कीमत प्रभावों के रूप में वास्तविक क्षति हो रही है जैसा कि कीमत कटौती और कीमत न्यूमीकरण से पता चलता है जिसकी वजह से लाभ में गिरावट आई है, लगाई गई पूंजी पर लाभ एवं नकद लाभ आदि में कमी आई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है सम्बद्ध देशों में सम्बद्ध वस्तु के लिए क्षमताएं भारत में मांग की तुलना में काफी अधिक हैं और तदनुसार प्राधिकारी द्वारा लगाए गए पाठनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाठन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। समीक्षा जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई सतत क्षति का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद है।

### निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

19. समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट कर लेने के उपरांत प्राधिकारी पाठनरोधी नियमावली के नियम के साथ पठित अधिनियम की 23 )क9 धारा5 के संबंध में लागू द्वारा वस्तुद्वारा देशों के मूल की या वहां से निर्यातित सम्बद्धके अनुसार प्राधिकारी सम्ब ( ऐसे को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने के कि क्या पाठनरोधी शुल्क

शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए एतद्वारा निर्णयिक समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

### प्रक्रिया

20. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी गई है :

- I. इस समीक्षा में यथा संशोधित दिनांक 24.11. की 2009अधिसूचना सं .14/06/2008 के तहत प्रकाशित जांच परिणामों के सभी पहलू शामिल हैं।
- II. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि जनवरी 1, 2013 से रदिसम्ब 31, 2013(तक की (माह 12 है। तथापि, क्षति जांच अवधि पर अप्रैल 1, 2010 से जांच अवधि की समाप्ति तक अर्थात् 2009-11, 2011-12,2012 - और जांच अवधि के रूप में विचार किया गया है। 13
- III. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, के उपबंध इस समीक्षा में 20 और 19 क परिवर्तनों सहित लागू होंगे।आवश्य

### सूचना प्रस्तुत करना

21. संबद्ध देश में निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के जरिए उसकी सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**

**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

**वाणिज्य विभाग,**

**कमरा सं .240, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011**

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग स-१े जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार से यह अपेक्षा की जाती है कि उसका अगोपनीय रूपांतरण अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए।

### समय सीमा

23. घरेलू उद्योग से सूचना प्राप्त होने के बाद ऐसे सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिनके पते उपलब्ध हैं, को लिखित में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए एक पत्र के जरिए सलाह दी जाएगी जो ऐसा पत्र जारी होने की तारीख से चालीस दिनों )40 दिन हितबद्ध पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए। ऐसा कोई अन्यसे पूर्व उपर्युक्त ( पक्षकार, जिसका पता उपलब्ध नहीं है, भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिन के भीतर 40 त की जानी चाहिए। जहां तक त कर सकता है। सूचना हार्ड कापी और साफ्ट कापी में प्रस्तुसूचना प्रस्तु/णियांटिप्प ता की उपयुक्तहेतु प्रतिनिधिक देश के रूप में कोरिया गणराज्य .गण.इस अधिसूचना में यथाउल्लिखित चीन जन णियां भेज देंके भीतर टिप्प

### गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई अनुरोध (अनुबंध सहित/ परिशिष्टउसके साथ संलग्न) करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के बारे में "गोपनीयता" का दावा किए जाने की स्थिति उसे दो अलग अलग सैटों-

शीर्षक) गोपनीय रूप से अंकित (क), पृष्ठ संख्या, सूची आदि और (

शीर्षक) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (ख), पृष्ठ संख्या, सूची आदिमें दाय (र करना अपेक्षित है।

25. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। किसी अंकन के बिना किया गया कोई अनुरोध अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों रूपांतरणों की हार्ड कापियों सहित साफ्ट कापियों के प्रत्येक के पांच )5त करने अपेक्षित होंगे। सैट प्रस्तु (

26. गोपनीय रूपांतरण में ऐसी सभी सूचना निहित होगी जो गोपनीय स्वरूप की है और सूचना अथवा ऐसी अन्य/ निहित होगी जिसके बारे में ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना, जिसके बारे में गोपनीय होने का दावा किया जाता है अथवा ऐसी सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, के लिए सूचना प्रदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित करण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

27. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ (वहार्य न होयदि सूचीकरण व्य) छोड़ी गई सूचीबद्ध या रिक्त : गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है, तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

28. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

29. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं।

30. संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसे सूचना प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

31. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### असहयोग

32. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे दीपक .एस.  
निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th April 2014

**Initiation**

(Sunset Review)

**Subject :** Initiation of Sunset Review Investigation of Anti-dumping duty on import of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel from China PR, Korea RP, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA

**No 15/04/2014-DGAD.**—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended, the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti-dumping Duty on imports of Cold-rolled Flat products of stainless steel of the width of 600 mm upto1250mm of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4mm originating in or exported from China PR, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA (hereinafter also referred to as Subject Countries) vide Final Findings Notification No. 14/06/2008-DGAD dated 24.11.2009. On the basis of the said findings, the Central Government imposed definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from subject countries vide Notification No. 14/2010—Customs dated 20.2.2010. Earlier, the Authority vide its Preliminary findings No.14/06/2008-DGAD dated 27<sup>th</sup> March, 2009 and corrigendum dated 22<sup>nd</sup> April 2009 recommended imposition of anti-dumping duties against dumped imports of the subject goods from the subject countries and provisional anti dumping duties were imposed by the Central Government vide custom notification No. 38/2009-Customs dated 22<sup>nd</sup> April, 2009, further amended by Notification No. 56/2009- Customs dated 30<sup>th</sup> May, 2009. The Authority carried out a mid-term review of the anti dumping duty imposed on subject countries and final findings was issued vide notification no 15/16/2010-DGAD dated 8.6.2011 and on the basis of the said findings, the Central Government imposed anti-dumping duties on the subject goods imported from subject countries vide Custom Notification No. 86/2011 dated 6.9.2011. Following the orders of the Hon'ble Punjab & Haryana High Court, the Designated Authority issued an order by the way of corrigendum notification whereby certain amendments were made in the products earlier excluded from the purview of the anti-dumping duties vide Corrigendum dated 5.12.2011. The Central Government vide corrigendum notification dated 7.2.2012 notified the revised Final Findings of the Authority.

**Request for Review**

2. WHEREAS in terms of Section 9A(5) the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. And, whereas, in terms of the above provisions, M/s Jindal Stainless Limited, a major manufacturer of subject goods in India, approached the Authority with a duly substantiated application requesting for sunset

review of the anti-dumping duties earlier imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries vide Ministry of Finance Notification No 14/2010-Customs dated 20.2.2010 (as amended) and sought the continuation of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries. The request is based on the grounds that dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries has continued in spite of the imposition of anti-dumping duties on the import of the subject goods from the subject countries and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject countries. The applicant has further argued that the expiry of the measure against the subject countries would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

4. And, the Authority on the basis of prime facie evidence given by the applicant considers that initiation of sunset review proceedings for the anti-dumping duties in force would be appropriate to examine the need for continuation of such duties to offset dumping from the subject countries and to examine as to whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur if the duties were removed or varied.

#### Domestic Industry and Standing

5. The application has been filed by M/s Jindal Stainless Limited (hereinafter referred to as the domestic industry or the applicant), major producer of the subject goods. There are three other companies producing the subject goods namely M/s BRG, M/s Shah Alloys and M/s Salem Steel Plant. As per the information available on record, the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production and also satisfies the requirement of standing to file the present sunset review application. The applicant also constitutes the domestic industry within the meaning of the term in Rule 2(b).

#### Product under Consideration and Like articles

6. In the original investigations, the Designated Authority in its final recommendations restricted the scope of duty on widths upto and inclusive of 1250mm only. The product under consideration was defined as follow:

*"Cold Rolled flat products of stainless steel the width of 600 mm upto 1250 mm of all series further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4 mm.*

*The subject goods will have the following exclusions from the scope of the product:*

- i. Grade AISI 420 High carbon (0.28%-0.40%), Grade 420, Grade 430 BA supplied by M/s Thyssenkrupp Stainless International, Germany, Grade AISI 441 and Grade AISI 443.
- ii. Duplex Stainless Steel grades 2205 (S31803), 2304 (S32304), EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318 and 1.4833 and Ferritic Grades EN 1.4509 and 1.4512.
- iii. Product supplied under Indian Patent no. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing chromium Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan)."

7. Subsequently, the Domestic Industry filed an application for mid-term review. Based on the application and after following due process of law, the Designated Authority recommended its Final Findings (Mid-term Review) vide notification No. 15/16/2009-DGAD dated 8.6.2011 whereby the following amendments to the product under consideration was made.

*"(a): Width tolerance of (+) 30mm shall apply to Mill edged, Cold-rolled flat products of stainless steel of specified width of 1000mm or more but not exceeding 1250 mm.*

*(b): Width tolerance of (+) 4mm shall apply to Trim edged Cold rolled flat products of stainless steel of specified width exceeding 1000mm but not exceeding 1250mm."*

8. Further, the Designated Authority carried out a review in terms of the orders of the Hon'ble Punjab & Haryana High Court as a consequence of which certain amendments were made in the products earlier excluded from the purview of the anti-dumping duties vide Corrigendum dated 5.12.2011. In view of the aforesaid, the product under consideration for the purpose of this review stands defined as follows:

*"Cold-rolled Flat products of stainless steel of width of 600 mm upto1250mm of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edged and +4mm for Trimmed Edged)"*, excluding the following:

- i. The subject goods of width beyond 1250 mm (plus tolerances).

- ii. Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509
- iii. Product supplied under Indian Patent No. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan).

The said products fall under Heading 7219.00 of the Customs Tariff Act, 1975. It is used for manufacture of White Goods, Process Equipment, Dairy Equipment, Automotive Components, Rail Cars, Metro Coaches, Architecture, Building, kitchen products & Construction etc.”

9. The scope of the product under consideration in the investigation shall remain the same as the scope of the product under consideration in the original final findings as amended during the mid-term review, and as per orders passed by Designated Authority in pursuance with the order passed by Hon’ble Punjab & Haryana High Court.

10. Further, the applicant submitted that the product manufactured by the domestic industry and the subject goods imported into India from the subject countries are like articles within the meaning of the Anti-dumping Rules; that there is no known difference between the subject goods imported from the subject countries and that produced by the domestic industry; that the subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods; that the consumers can use and are using the two interchangeably and that the two are technically and commercially substitutable. After examination, the Authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are like article to that imported from the subject countries.

### **Subject Countries**

11. The present application has been filed in respect of alleged continued dumping of the product under consideration from China PR, Korea RP, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA (hereinafter also referred to as Subject Countries)

### **Normal value**

12. It has been claimed by the petitioner that China PR being a non-market economy country under the Indian Anti-dumping Rules, the normal value for China PR is required to be determined as per the procedure described in Para 7 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules. It has been claimed that for the purpose of determination of normal value in case of a non-market economy country, an appropriate third market economy country is required to be selected as the first alternative. The petitioner has proposed that South Korea be taken as an appropriate market economy third country. The domestic industry has claimed that the average capacity of plants, the cost structure, the production process and the technology are reasonably and fairly close to that found in China and also the fact that the fact that South Korea is a market economy country with considerable competition within the local producers as well as from imported goods. The normal value for China PR has been claimed on the basis of the prices quoted for South Korea in the MEPS Stainless Steel review (Monthly metal bulletin) for 300 and 400 series along with adjustments. However, for the purpose of initiation, the normal value for subject goods for China PR has been determined by constructing normal value based on the available information i.e on the basis of the information made available by the domestic industry.

13. The petitioners for the purpose of determining normal value of product under consideration in Taiwan, Korea RP, USA, and EU have referred to the prices quoted in the MEPS Stainless Steel review (Monthly metal bulletin) for 300 and 400 series along with adjustments. It has also been claimed by the petitioners that they were not able to get the published prices for Thailand and South Africa so they have claimed normal value in these two subject countries by taking MEPS Stainless Steel review (Monthly metal bulletin) for 300 and 400 series along with adjustments for Taiwan and EU respectively.

14. It is noted that the applicant has not able to obtain the prices of 200 series and Duplex from any reliable source. Therefore, the applicant has constructed the normal value of 200 Series and Duplex for all the subject countries by constructing normal value based on the available information.

15. The Authority, after examination, considers that there is sufficient *prima facie* evidence of normal

value of the subject goods in the subject countries.

#### **Export Price**

16. Petitioners have determined the export price by using information from Cybex Exim, to assess the volume and value of imports in India. Price adjustments have been made on account of Ocean Freight, Marine insurance, Inland transportation and sales commission. The Authority, after examination, considers that there is sufficient *prima facie* evidence of export price of the subject goods in the subject countries.

#### **Dumping Margin**

17. Petitioner has provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, *prima-facie*, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries continue to be dumped, to justify initiation of a review investigation.

#### **Continuation or Recurrence of Dumping and Injury.**

18. The petitioners have claimed that domestic industry continues to suffer material injury by way of adverse price effects as evidenced by price undercutting and price suppression leading to deterioration in profits, decline in return on capital employed and cash profits, etc. The petitioner has claimed that capacities in subject countries for subject goods are substantially huge in comparison of the demand in India and accordingly there is likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry once the Anti-dumping duties levied by the Authority are withdrawn. The Authority considers that there is sufficient *prima facie* evidence of continued injury caused to the domestic industry by dumped imports from subject countries to justify initiation of a review investigation.

#### **Initiation**

19. Having satisfied itself on the basis of the positive *prima facie* evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a Sunset Review in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of Anti-dumping Rules, to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

#### **Procedure**

20. The following procedure has been followed.

- i. The review will cover all aspects of the final findings of the original investigations published vide Notification No. 14/06/2008-DGAD dated 24.11.2009 as amended.
1. The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1<sup>st</sup> January, 2013 to 31<sup>st</sup> December, 2013 ( 12 months). The injury investigation period has however, been considered as the period from 1st April 2009 to the end of the POI, that is, 2010-11, 2011-12, 2012-13 and POI.
- ii. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

#### **Submission of Information:**

21. The exporters in subject country, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned would be addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

**The Designated Authority**  
**Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties**  
**Ministry of Commerce & Industry**  
**Department of Commerce**  
**Room No. 240, Udyog Bhawan**  
**New Delhi -110011**

22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

#### **Time Limit:**

23. On receipt of information from domestic industry, all interested parties, whose addresses are available, would be advised through a letter to offer their comments in writing so as to reach the Authority at

the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/ information within 40 days from date of publication of this notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies. With regard to sending the comments on the appropriateness of Korea RP as surrogate country for China PR as mentioned in this notification, the interested parties are required to send the comments within 14 days from the date of notification.

Submission of information on confidential basis

24. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

- (a) One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- (b) The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

25. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

26. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

27. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

29. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

30. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File:

31. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

32. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S DEEPAK, Designated Authority